वाइब्रेंट विलेजेज : सीमावर्ती गांवों के विकास से सुरक्षित होता भारत

सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

16-30 अप्रैल, 2023 वर्ष-1 अंक-2

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

ट्वीट्स	04
सतर्कता और तत्परता से निकल रहा समाधान	08
ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और सैटेलाइट का होगा उपयोग	11
विकास और प्रोत्साहन की बहार	13
असम-अरुणाचल में समझौते से हुआ समाधान	20
सुरक्षा के साथ विकास	23
सीमावर्ती क्षेत्र का सर्वांगीण विकास	30

विशेष रिपोर्ट

05 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत

16 'गागर में सागर' है 'मन की बात'

24 वाइब्रेंट विलेजेज

संपादक की कलम से

श्री बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः।'

ऋग्वेद का यह स्वस्ति वाचन कहता है कि हमारे लिए सभी ओर से कल्याणकारी विचार आएं।

हम इसे हर पल आत्मसात करते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का यह मूलमंत्र है। हमारी सरकार भी सबको साथ लेकर समेकित विकास की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रतिपल क्रियाशील है। वसुधैव कुटुम्बकम् को जी-20 के प्रतीक चिन्ह के साथ समाहित किया गया है। साल 2023 ऐतिहासिक वर्ष है।

बीते साल जब सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के साथ दो दिन तक चिंतन शिविर में संवाद किया, तो कई मुद्दों पर समग्रता से चर्चा हुई। अब तक जिन सीमांत गांवों को देश का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसे 'प्रथम' कहने का आह्वान किया। उन्हें वाइब्रेंट विलेज बनाने की बात हुई। बजट में सरकार ने उसके लिए व्यवस्था भी की है। हाल ही में श्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में इससे जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। वाइब्रेंट विलेज में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में शामिल इन गांवों से भारत तिब्बत सीमा पुलिस का पुराना नाता रहा है।

> अब तक जिन सीमांत गांवों को देश का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसे 'प्रथम' कहने का आह्वान किया। उन्हें वाइब्रेंट विलेज बनाने की बात हुई।

विकास के साथ कुछ अनचाही चीजें भी साथ चलती हैं। देश में हो रहा मादक पदार्थों का कारोबार ऐसा ही एक अनचाहा सच है। लेकिन हमारे पुलिस बलों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तत्परता से इसे बहुत अधिक फलने-फूलने का अवसर नहीं मिलता। बीते दशक में एजेंसियों की कार्रवाई से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सूरजकुंड में हुए दो दिन के चिंतन शिविर में इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। एनआईए जैसी एजेंसी के काम की सराहना हर मंच से हो रही है। महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई, तो बीते कुछ सालों में की गई नई पहलों से लोगों में नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हाल के नौ वर्षों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशन में कई सकारात्मक कार्य संपादित हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार-बार कहते हैं कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब वर्ष 2047 के लिए, हर विभाग अपना लक्ष्य तय करे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 2047 के लिए अपने लक्ष्य तय किए हैं। आंतरिक सुरक्षा, सरहद की सुरक्षा और आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का समन्वय करते हुए रूपरेखा बनाई जा रही है।

हमें पूरी उम्मीद है कि 'सजग भारत' का पहला अंक आपको मिला होगा। दूसरा अंक आपके हाथ में है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो हर पंद्रह दिन में आप तक नए अंक के साथ पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिबद्धता को आपकी प्रतिक्रियाओं से संबल मिलेगा।

आप अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें। हमारा ई-मेल है – dg@bprd.nic.in

जय हिंद

Let us reiterate our commitment to #ShareFactsOnDrugs and realise our vision of a Drugs Free India. Remember- addiction is neither cool nor a style statement. Sharing an old #MannKiBaat episode which contained many aspects of overcoming the drugs menace.

- Sh. Narendra Modi, *Prime Minister of India*

ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं और हम इसे अवश्य जीतेंगे। नशामुक्त भारत ही आने वाली पीढ़ी को हमारा सबसे बड़ा उपहार होगा।

-श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

9 अप्रैल, 1965 को सरदार और टाक पोस्ट पर देश की सुरक्षा में अपने साहस तथा पराक्रम का परिचय देते हुए सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले @crpfindia के अमर बलिदानियों को नमन। देश अपने सीआरपीएफ के जवानों के बलिदान और पराक्रम को शौर्य दिवस के रूप में याद करता है।

- श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

India has achieved a remarkable feat by running the world's largest financial inclusion program, empowering women through access to bank accounts. Over 26 crore accounts have been opened, enabling #NariShakti and making a significant impact on the lives of women in #NewIndia.

- Sh. Nisith Pramanik, *Minister of State (Ministry of Home Affairs and Ministry of Youth Affairs & Sports)*

India's digital revolution is empowering the underprivileged, unlocking new opportunities for their growth, and bridging the gap between the rich and the poor

- Sh. Ajay Mishra, *Minister of State (Ministry of Home Affairs)*

In a landmark decision under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, MHA approves conduct of Constable (General Duty) examination for CAPFs in 13 regional languages in addition to Hindi and English.

-Ministry of Home Affairs

2047 तक नशा मुक्त होगा भारत

नशा मुक्त भारत आने वाली पीढ़ी को हमारा सबसे बड़ा उपहार

देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है। केंद्र सरकार की ओर से स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में देश को नशामुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री बनते ही साल 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्ति के लिए पूरे समाज से आह्वान किया था। देश के गृह मंत्री के रूप में श्री अमित शाह बीते तीन साल में नशा कारोबारियों की कमर तोड़ने का काम करते आ रहे हैं। हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने पूरे देश में नशामुक्ति के लिए शंखनाद कर दिया है।

» ब्यूरो

साल 2014 में अपने मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब हम किसी युवा को नशा करते देखते हैं तो उसे बुरा-भला कहते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वह युवा बुरा नहीं है बल्कि बुराई तो ड्रग्स में है, नशे में है। पूरा देश मिलकर 'ड्रग्स फ्री इंडिया' कैंपेन चलाए। फिल्म, क्रिकेट और अन्य क्षेत्रों की सिलेब्रिटीज भी नशे पर जागरूकता अभियान चलाएं। युवा पीढ़ी इस दलदल से बाहर आए इसके लिए पूरे समाज को चिंता करनी होगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर के Drugs Free India hash-tag के साथ एक लगातार अभियान चला सकते हैं। क्योंकि दुनिया से जुड़े हुए ज्यादातर बच्चे सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। अगर हम Drugs Free India hash-tag, को आगे बढ़ायेंगे तो लोक शिक्षा का एक अच्छा माहौल हम खड़ा कर सकते

'मन की बात' में ये कहा था प्रधानमंत्री ने

ड्रग्स, नशा ऐसी भंयकर बीमारी है, ऐसी भंयकर बुराई है जो अच्छें-अच्छें को हिला देती है। मैं जानता हूँ कि बालक जो इस बुराई में फंसता है तो कभी-कभी हम उस बालक को दोषी मानते हैं। बालक को बुरा मानते हैं। हकीकत ये है कि नशा बुरा है। बालक बुरा नहीं है, नशे की लत बुरी है। बालक बुरा नहीं है हम अपने बालक को बुरा न माने। आदत को बुरा मानें, नशे को बुरा मानें और उससे दूर रखने के रास्ते खोजें। बालक को ही दुत्कार देगें तो वो और नशा करने लग जाएगा। ये अपने आप में एक Psycho-Socio-Medical Problem है। और उसका हमें Psycho-Socio-Medical Problem के रूप में ही निदान करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब जीवन में निराशा आ जाती है, विफलता आ जाती है, जीवन में जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तब आदमी नशे की लत में पड़ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ऊंचे इरादे नहीं हैं, एक वैक्यूम है, वहां पर ड्रग का प्रवेश करना सरल हो जाता है। ड्रग से अगर बचना है, अपने बच्चे को बचाना है तो उनको ध्येयवादी बनाइये, कुछ करने के इरादे वाले बनाइये, सपने देखने वाले बनाइये। आप देखिये, फिर उनका बाकी चीजों की तरफ मन लगेगा। उसको लगेगा नहीं कि मुझे नशा करना है। मुझे स्वामी विवेकानन्द के वो शब्द याद आते हैं। हर युवा के लिए वो बहुत सटीक वाक्य है और मुझे विश्वास है कि वाक्य, बार-बार गुनगुनायें स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है-एक विचार को ले लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो। उस विचार को जीवन में उतार लो। अपने दिमाग, मांसपेशियां, नसों, शरीर के प्रत्येक हिस्से को उस विचार से भर दो और अन्य सभी विचार छोड़ दो।

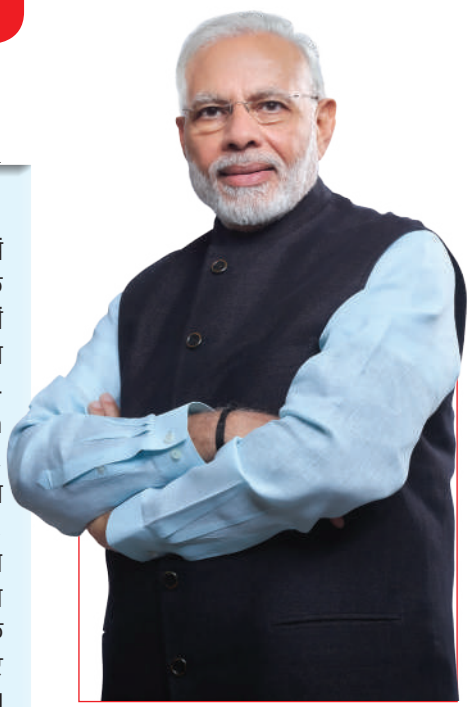

> मैं नशे में डूबे उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी सोचा है कि जिन पैसों से आप ड्रग्स खरीदते हैं, वो पैसे कहां जाते हैं ? 3 बुराइयों वाला है ड्रग्स -Darkness, Destruction and Devastation. न ये स्टाइल स्टेटमेंट है और न ये कूल है, हकीकत में नशा बर्बादीका मंजर है। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है और बर्बादी तक पहुंचा देता है।
>
> **- श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

हैं। दो नवंबर, 2014 को 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ लोगों ने उन्हें नशे की लत के बारे में लिखा है। उन्होंने तब लोगों से इस मुद्दे पर अपने विचार एवं सुझाव साझा करने को कहा था।

इसके बाद से ही सरकार की ओर से नशामुक्ति को लेकर प्राथमिकताएं तय की जाने लगी। कार्य योजनाओं पर विस्तार से विमर्श और क्रियान्वयन होता रहा। 19 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2047 में हम नशामुक्त भारत का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि नशामुक्त भारत आने वाली पीढ़ियों और देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम नशे के खिलाफ लड़ाई में एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं कि यहां से दृढ़ संकल्प, सामूहिक प्रयासों, Team India और Whole of Government अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारी विजय निश्चित है। श्री अमित शाह ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई कठिन जरूर है, लेकिन हम सभी को मोदी जी के 2047 में नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प करना होगा और आगे बढ़ना होगा।

नशा मुक्ति को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों की बात करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कुछ आंकड़ों को लोगों के सामने रखा। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार, पिछले 3 सालों में नशे के खिलाफ लड़ाई के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि 2006-2013 के बीच कुल 1257 मामले दर्ज किए गए थे जो 2014-2022 के बीच 181 प्रतिशत बढ़कर 3544 हो गए। इसी अवधि में कुल गिरफ्तारी की संख्या 1363 के मुकाबले लगभग 300 प्रतिशत बढ़कर 5408 हो गई। 2006-2013 के दौरान 1.52 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई थी जो 2014-2022 के बीच दोगुना बढ़कर 3.73 लाख किलोग्राम हो गई। 2006-2013 के दरम्यान 768 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स जब्त की गई थी जो 2014-2022 के बीच 25 गुना से अधिक बढ़ोतरी के साथ 22 हजार करोड़ रुपए हो गई।

सूचना तकनीक के इस समय में दोषियों के खिलाफ तकनीकी रूप से सक्षम होना होगा। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस ओर भी इशारा किया। उनका कहना था कि नशे के खिलाफ लड़ाई में 2 महत्वपूर्ण शस्त्र हमारे पास हैं- PITNDPS और संपत्ति को जब्त करना। ड्रग्स के कारोबारियों के खिलाफ Ruthless होकर कार्रवाई करनी चाहिए, तभी इस लड़ाई को गति मिलेगी। राज्यों को डार्क नेट और क्रिप्टो करंसी के उपयोग पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ-साथ ब्लॉक चेन विश्लेषण, मैप इंटेलीजेंस और डिजिटल फॉरेंसिक जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए भी सभी राज्यों को राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम इन तकनीकों के लिए अच्छे से काम करते हैं, तो हम इस लड़ाई में हम खुद को 2 कदम आगे पाएंगे।

केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए कई नई शुरुआत भी की गई हैं। देश में अवैध खेती की पहचान और उसे नष्ट करने के लिए 'मैप ड्रग्स' मोबाइल एप और वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। ये सारे कदम नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई को गति देने वाले साबित होंगे। पुलिस आधुनिकीकरण और एफएसएल के अपग्रेडेशन के लिए मिलने वाली केन्द्रीय निधियों का उपयोग नार्को रिलेटेड एफएसएल अपग्रेडेशन करने के लिए भी करना चाहिए। एनडीपीएस के वाणिज्यिक

बेहद अहम है राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल

पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार जो सुविधाएं देगी, उनमें पहली प्राथमिकता नारकोटिक्स को देनी चाहिए। राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल (NCORD) की चारों बैठकें, 2 केन्द्रीय और 2 राज्य स्तर पर नियमित रूप से होनी चाहिए, सबसे जरूरी बैठक ज़िला स्तर की है। हर राज्य को एकसमान प्रयास करने चाहिए कि ज़िलास्तरीय बैठकें हों। श्री शाह ने कहा कि केन्द्रीकृत NCORD पोर्टल पर अगर सारी सूचनाएं अपलोड की जाती हैं, तो Knowledge Management System के रूप में सभी को मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क तक हमारी जांच जरूर पहुंचनी चाहिए और उस नेटवर्क के किसी भी हिस्से के भाग को नष्ट करने की ज़िम्मेदारी सभी एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों की है। ज़िले और राज्य का ड्रग्स नेटवर्क चार्ट जरूर बनाना चाहिए, जिससे हमें समस्या के फैलाव और अपनी लड़ाई को केन्द्रित करने के बारे में जानकारी मिलेगी। व्यवस्था को सफलता में बदलने के लिए हमें अपनी संवेदना को इसके साथ जोड़ना होगा। समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए केन्द्रीय ऐजेंसियों और तटीय राज्यों एवं स्थानीय जनता के बीच बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए।

मामलों की जांच करने के लिए ईडी और अन्य एजेंसियों को मामले रेफर करने चाहिए। हमारा जोर संपूर्ण नेटवर्क को ध्वस्त करने पर होना चाहिए। इसके अलावा हमें पुनर्वास और जन-जागरूकता अभियान से भी खुद को जोड़ना होगा जिससे हमें बहुत फायदा मिलेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के विकास की नींव होती हैं और नारकोटिक्स इन पीढ़ियों को खोखला कर देता है और अगर देश के विकास की नींव ही खोखली हो, तो इस पर एक मजबूत देश की रचना नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के साथ-साथ देश के अर्थतंत्र पर भी अपना दुष्प्रभाव डालता है। नारकोटिक्स की तस्करी देश के अर्थतंत्र के साथ-साथ नार्को टेरर के माध्यम से देश की सीमाओं और उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करती है। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समाज में नशीले पदार्थों के खतरे को समाप्त करने के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा, 'समाज में नशीले पदार्थों के खतरे को समाप्त करने के प्रयासों में समन्वय और तत्परता लाने की अच्छी पहल।'

इससे पहले भी 24 मार्च को बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि राज्यों, एजेंसियों और लोगों के बीच बेहतर सहयोग और तालमेल से देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को खत्म करने में मदद मिल सकती है। मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई एक जन आंदोलन बन जाना चाहिए तथा प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय समाज

> ' हमें 'बॉटम टू टॉप' और 'टॉप टू बॉटम' के अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा और नशे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। नशे के खिलाफ लड़ाई कठिन जरूर है, लेकिन हम सभी को 2047 में नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प करना होगा और आगे बढ़ना होगा।'
>
> **-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

को वर्ष 2047 तक नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने 24 मार्च को पटना, तमिलनाडु, कोच्चि, बेंगलुरु और दिल्ली में जब्त की गई एक हजार दो सौ 35 करोड़ रुपए के नौ हजार दो सौ 98 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया और कहा कि अगर मादक पदार्थों का पता लगाया जाता है, मादक कार्टेल के नेटवर्क को नष्ट किया जाता है और देश में अपराधियों के पुनर्वास और नशीली दवाइयों का सेवन करने वाले के पुनर्वास में तेजी आती है, तो भारत एक विकसित देश बन सकता है। ■

सतर्कता और तत्परता से निकल रहा समाधान

देश में नशे पर लगाम लगाने के लिए नई प्रौद्योगिकी व डिजिटल मोड्स का उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत को नशा मुक्त करने का आह्वान किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशा माफिया की जड़ों तक पहुंचकर प्रभावी कदम उठा रहा है।

» ब्यूरो

अपने साथियों को नशे के लिए 'NO' कहने की हिम्मत कीजिए। ये गलत कर रहे हो, ये कहने की आप हिम्मत जताइए। न ये स्टाइल स्टेटमेंट है और न ये कूल है, हकीकत में नशा बर्बादी का मंजर है। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है और बर्बादी तक पहुंचा देता है। युवा को भी सोचना होगा कि जिस बुराई को वह खरीद रहा है, कहीं उनका पैसा उनके स्वास्थ्य के साथ ही पूरे देश और समाज को भी तबाह तो नहीं कर रहा है? नशीली दवाओं पर खर्च हुए उसके पैसे से ड्रग्स माफिया अपना जाल फैला सकते हैं और आतंकवादी हथियार खरीदकर सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों का खून बहा सकते हैं।

अपने 'मन की बात' कार्यक्रम से जब इस प्रकार का आह्वान स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो पूरा देश बड़े गौर से सुनता है। सरकारी एजेंसी एक्टिव मोड में आती है और लगातार इस पर काम किया जाता है। देश के युवाओं को मादक पदार्थों की चपेट में आने से रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने कई कदम उठाए हैं और इसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सतर्कता बढ़ाने के साथ-साथ अपनी कार्यप्रणाली बदली है। इसके अलावा इस एजेंसी ने अन्य एजेंसियों के साथ अपना तालमेल बढ़ा कर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। प्रधानमंत्री ने यह आह्वान नवंबर 2014 को हुए 'मन की बात' कार्यक्रम में किया था।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2006 से वर्ष 2013 के 8 साल के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देश में कुल 1257 मामले दर्ज किए थे। लेकिन एनसीबी की तरफ से बढ़ाई गई सतर्कता से दर्ज मामलों की संख्या में तेज वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के बीच कुल 3172 मामले दर्ज किए गए और इन पर कार्रवाई हुई।

अक्टूबर, 2022 में हरियाणा के फरीदाबाद के निकट सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और पिछले 8 वर्षों में 3 हजार केस दर्ज किए गए हैं, जबकि लगभग 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की ड्रग्स जब्त की गई है। नारकोटिक्स की समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से 372 जिले चिन्हित किए गए हैं। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का कहना है कि नारकोटिक्स के खिलाफ एकाग्रता के साथ विशिष्ट तरीकों और तीव्र गति से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। पुलिस थानों को भी लड़ना पड़ेगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी लड़ना पड़ेगा, स्टेट की नारकोटिक्स कंट्रोल एजेंसियों को भी लड़ना होगा, कोस्टगार्ड को भी

अवेयर करके, हमें उनको साथ लेना पड़ेगा, नौसेना को भी साथ लेना पड़ेगा, एयरपोर्ट ऑथोरिटी और एयरपोर्ट को भी साथ लेना पड़ेगा।

कुछ राज्यों में आज भी गांजा की खेती एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार की ओर से यह बात सामने आई कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ-ईस्ट और दक्षिण के छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करना चाहिए और कड़ाई के साथ गांजे की खेती को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन मैपिंग का उपयोग कर गांजे की खेती को समाप्त करने का आह्वान किया।

ध्यान देने योग्य यह भी है कि समुद्र के किनारे बसे गुजरात में समुद्र के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी की कई घटनाएं सामने आईं। नारकोटिक्स ब्यूरो की तत्परता से यदि गुजरात में समुद्र के जरिए, इतना अधिक ड्रग्स पकड़ी जा सकती है तो अन्य राज्यों में भी ऐसी दबिश संभव हैं। यदि गुजरात में अधिक ड्रग्स पकड़ी जा रही है, तो इसका मतलब है कि वहां की एजेंसियां ज्यादा सजग हैं। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री ने पंजाब का भी ज़िक्र किया कि यदि वहां ड्रग्स की बड़े पैमाने पर बरामदगी नहीं हो रही है, तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि वहां यह समस्या ही नहीं है।

चंडीगढ़ स्थित द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की एक स्टडी के अनुसार, पंजाब में हर सातवां व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है। यानी 15.4 फीसदी आबादी ड्रग एडिक्ट हो चुकी है। यह स्टडी पीजीआई के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने की है। कुछ समय पहले भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक सर्वे किया था। इसके अनुसार पंजाब में ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2,32,856 है। सर्वाधिक 53 फीसदी (123413) लोग हेरोइन और चिट्टे का नशा करते हैं। हेरोइन और चिट्टे का नशा करने के लिए औसतन एक युवक 1400 रुपए प्रतिदिन खर्च करता है।

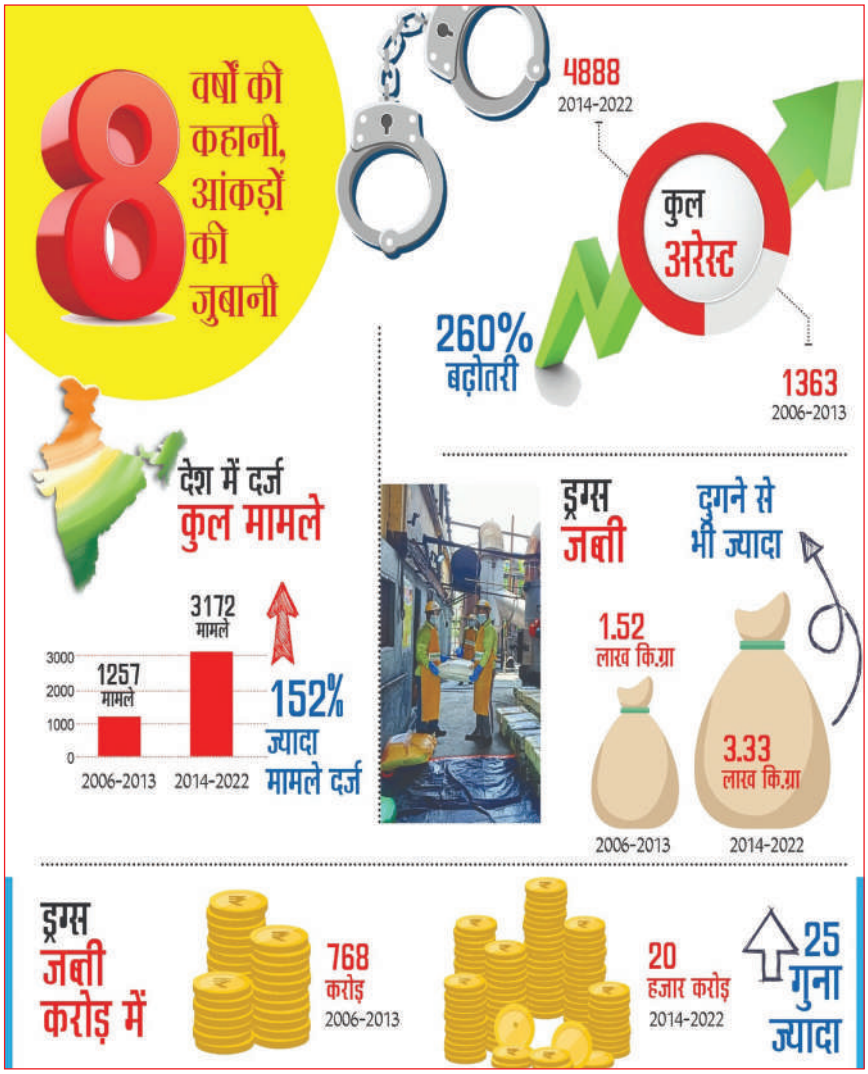

अहम बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की चर्चा कई स्तरों पर हुई है। उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और उसकी उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने तत्परता दिखाई है। राज्य सरकार ने अगस्त, 2022 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स को मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त अपराधियों, माफियाओं और गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई में सर्च सीजर, गिरफ़्तारी और विवेचना करने की सारी शक्तियां दी गई हैं। अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी थाने में अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए विवेचना स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। ■

डॉग स्क्वॉड का सहारा होगा कारगर

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कहते हैं, हर एयरपोर्ट व पोर्ट पर ट्रेंड डॉग स्क्वॉड हो। हर कोरियर-पार्सल वालों की रेंडम चेकिंग यदि हम डॉग स्क्वॉड के माध्यम से कराते हैं, तो इसको रोकने में हमें काफी फायदा मिलेगा।

ड्रग स्मगलिंग पर प्रहार

» ब्यूरो

नशा मुक्त भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए समय-समय पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी छापेमारी और जब्ती अभियान चलाती रहती है। बीते वर्षों में ड्रग्स नेटवर्क के चार्ट की भी मैपिंग की गई है और राज्यों में ड्रग्स आने के रास्ते और उसके नेटवर्क की 472 जिलों में मैपिंग करके राज्यों को भेज दी गई है। एनसीबी लगातार काम कर रहा है। 21 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में एक चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहाकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश में ड्रग्स की समस्या और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की थी। इस चर्चा में एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट, 2022 का उदाहरण दिया था। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट, 2022 में चेन्नई क्षेत्र द्वारा 11 किलो मेथमफेटामाइन की जब्ती और दिसम्बर, 2022 में मुंबई टीम द्वारा सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल जब्ती का जिक्र किया गया है। विशिष्ट सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने 7 फरवरी, 2022 को गुवाहाटी से गुम्मुदिपुंडी में आने वाली तमिलनाडु नंबर वाले एक ट्रक को रोका गया। एनसीबी की टीम ने ट्रक के ड्राइवर को पकड़ा और 11 किलो मेथमफेटामाइन की जब्ती हुई। ड्राइवर से पूछताछ में पता चला कि ट्रक का मालिक एक श्रीलंकाई नागरिक है। ड्राइवर को उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। हालांकि बाद में वी. कावेरी ट्रेवल्स की एक बस से चेन्नई जा रहे ट्रक के मालिक को पकड़ लिया गया। महाजर (पंचनामा) के दौरान पूछताछ की गई, जिसमें उसने कई नामों का जिक्र किया और उनके आपस के संबंधों की भी पोल खोली। इस पूछताछ के आधार पर एनसीबी की टीम ने एक अन्य श्रीलंकाई नागरिक की मेथमफेटामाइन की खरीद-फ़रोख्त में मध्यस्थता की पहचान की और उसके खिलाफ कार्रवाई की। चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। चेन्नई में रिसीवर के घर तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और 4,21,100 रुपए की भारतीय मुद्रा और 37,130 रुपए की श्रीलंकाई करेंसी की जब्ती हुई। इस प्रकार फाइनेंसर, आपूर्तिकर्ता और रिसीवर सहित पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। दूसरी बड़ी घटना एनसीबी, मुंबई क्षेत्र द्वारा कोडीन आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) की बोतलें और नाइट्राजेपम टैबलेट की जब्ती की है। गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी मुंबई क्षेत्रीय इकाई की एक टीम ने 09 दिसम्बर, 2022 को सेक्टर 14, कोपरखैरने, ठाणे नवी मुंबई में क्लोरोफेनरमाइन मैलेट और कोडीन फॉस्फेट सिरप फेनसाइरेस्ट कफ सिरप 100 मिलीलीटर की 920 बोतलों की जब्ती की और एक जोड़े को गिरफ्तार किया। उसी दिन इस मामले में एक और व्यक्ति को भी पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया और उसके खुलासों के आधार पर, एनसीबी मुंबई ने फिर से नाइट्राजेपू नाइट्राजेपम (नाइट्रावेट 10 मिलीग्राम) की 6000 टैबलेट वजन (3-6 किलोग्राम) और कोडीन फॉस्फेट और क्लोरफेरामाइन मालेट सिरप की सात बोतलें 10 दिसम्बर को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, काशीमीरा मीरा रोड (ई), ठाणे के एक पेट्रोल पंप में जब्त कीं और मामले के चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक के खुलासे के आधार पर एनसीबी मुंबई ने 12 दिसम्बर, 2022 को कांदिवली, मुंबई में क्लोरफेनरामाइन मैलेट और कोडीन फॉस्फेट सिरप फेनसाइरेस्ट कफ सिरप 100 एमएल की 480 बोतलें जब्त की गई और 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। आगे की जांच में छठवें आरोपी (आपूर्तिकर्ता) को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल, इस प्रकार की सैकड़ों कार्रवाई को एनसीबी पूरे साल भर में अंजाम तक पहुंचाता रहा है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बताया था कि ड्रग स्मगलिंग के केस को गंभीर प्रकार के मामले में डाला है और ड्रग स्मगलिंग डीलर्स के खिलाफ दर्ज किए गए 13000 केस यही बताते हैं कि हमारी दिशा सही है और परिणाम भी मिल रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में 61 नए साइटोट्रॉपिक पदार्थों को सरकार ने अधिसूचित किया है, जो पहले इस कैटेगरी में नहीं आते थे। ■

नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए त्रिसूत्रीय रणनीति बनाई है।

संस्थागत संरचना की मजबूती

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सिस्टम की मजबूती और एकाउंटेबिलिटी पर जोर देने के कारण गृह मंत्रालय द्वारा संस्थागत रिस्ट्रक्चरिंग और कानूनी प्रावधानों को मजबूती देने के सतत प्रयत्न किए गए है। इसके तहत वर्ष 2019 में बेहतर समन्वय एवं तालमेल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चार स्तरीय (शीर्ष स्तर, कार्यपालक स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर की समिति) एन-कोर्ड मेकेनिज्म का गठन किया गया। इसके साथ ही 25 मार्च 2022 को गृह मंत्रालय द्वारा चार स्तरीय **एनकॉर्ड** (NCORD) मैकेनिज्म को पुर्नगठित गठित किया गया। NCB को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी बनाया गया है।

नशामुक्त भारत

ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और सैटेलाइट का होगा उपयोग

गृह मंत्रालय किसानों को नुकसान पहुंचाए बिना बड़े पैमाने पर ड्रोन और नवीनतम तकनीक का उपयोग करके पहाड़ी और कठिन इलाकों में अवैध खेती को नष्ट करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन कर रहा है। अवैध फसलों की खेती में लगे किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका व्यवस्था पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है...

» ब्यूरो

देश को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत सरकार की ओर से अफीम पैदावार पर नियंत्रण के लिए ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। बीते दिनों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस लड़ाई में राज्यों को साथ लेकर एक सिनर्जी लाकर नारकोटिक्स से संबंधित सभी एजेंसियों को एक प्लेटफार्म पर लाना और राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना है कि देश ने अब इस समस्या की जड़ में जाकर इसका समाधान करने का मन बना लिया है। हमारा फोकस नेटवर्क को तोड़ने और सीमा पार से होने वाली तस्करी रोकने पर होना चाहिए। हमें किसी जब्ती में शामिल 'चेहरों' और ड्रग सेवन तथा वितरित करने वालों को पकड़ने से आगे जाना होगा और इनके पीछे सीमा के बाहर से भारत में ड्रग्स भेजने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा। साथ ही देश के अन्दर फैले नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा।

देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र चार देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है और अफीम

उत्पादक क्षेत्र म्यांमार के निकट है, जो दुनिया में अफगानिस्तान के बाद अफीम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पूर्वोतर भारत में ड्रग्स सेवन एक गंभीर समस्या है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, पूर्वोतर के सात राज्यों में अफीम और गांजे का सेवन खतरनाक स्तर पर है। यह देश में इनके सेवन के औसत से अधिक है। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोतर में इसके कुछ नए ट्रेंड्स सामने आए हैं। ड्रग सिंडिकेट उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित बैंक खातों और डाक पतों का फायदा उठाते हैं। मणिपुर में कुछ भारतीय बैंकों में म्यांमार के नागरिकों के बैंक खाते हैं। पूर्वोतर के ड्रग तस्करों की नाइजीरियाई लोगों के साथ मिलीभगत की बात भी सामने आई है।

इन सबकी रोकथाम के लिए सरकार ने उत्तर पूर्व राज्यों के लिए कई नई पहल की हैं। गुवाहाटी में NCB के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कर दी गई है। आगामी वर्षों में NCB चार राज्यों अर्थात असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में कार्य करेगा। त्रिपुरा के अगरतला और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट/लोअर सियांग में नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, सिक्किम से सटे क्षेत्र के बेहतर कवरेज के लिए न्यू जलपाईगुड़ी में जोनल कार्यालय भी शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में गांजा और अफीम पोस्त की अवैध खेती के खिलाफ कई उपाय किए गए हैं। गृह मंत्रालय किसानों को नुकसान पहुंचाए बिना बड़े पैमाने पर ड्रोन और नवीनतम तकनीक का उपयोग करके पहाड़ी और कठिन इलाकों में अवैध खेती को नष्ट करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन कर रहा है। अवैध फसलों की खेती में लगे किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका व्यवस्था पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। साथ ही एनसीबी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अफीम पोस्त की अवैध खेती को नष्ट करने के लिए उपग्रह इमेजरी साझा कर रहा है।

ड्रग्स के खिलाफ ई-प्रतिज्ञा लेने की पहल

प्रमुख ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी होने के अलावा, एनसीबी को राज्य के अधिकारियों और हितधारकों के समन्वय में ड्रग के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि mygov.in वेबसाइट पर 'जीवन को हां, ड्रग्स को ना' शीर्षक से एक ई-प्रतिज्ञा अपलोड की गई।

इस संकल्प का उद्देश्य नागरिकों के बीच ड्रग्स के दुष्प्रभाव का संदेश फैलाना है ताकि वे भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने और स्वस्थ जीवन का संकल्प दिखा सकें। इस लिंक http://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse के माध्यम से नागरिक ई प्रतिज्ञा ले सकते हैं।

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय जैसे समाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, CAPF और पुलिस तथा राज्य प्राधिकरण सहित अन्य सहयोगी एजेंसियों को ई- प्रतिज्ञा के बारे में जागरूक किया गया और अनुरोध किया गया कि इस जानकारी को शिक्षण संस्थानों सहित पूरे समाज में प्रसारित किया जाए, ताकि नशे के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाया जा सके।

एनसीबी ने संबधित क्षेत्रीय कार्यालयों के मार्गदर्शन में मिशन मोड में चयनित स्कूलों और कॉलेज/शैक्षिक संस्थानों में अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिज्ञा-बद्ध परिसर (ड्रग के खिलाफ आंदोलन) की शुरूआत भी की है। 2022 के अंत तक लगभग 30 लाख लोगों ने नशे के खिलाफ यह ई-प्रतिज्ञा ली। ■

एनसीबी द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

माह 2022	जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
जनवरी	34	9187
फरवरी	30	2119
मार्च	23	2557
अप्रैल	25	1822
मई	27	2420
जून	307	06144
जुलाई	32	5914
अगस्त	23	1490
सितंबर	15	2630
अक्टूबर	19	3430
नवंबर	19	4712
दिसंबर	20	7695
कुल	574	150120

एनसीबी द्वारा अन्य कार्यक्रम

ड्रग निषेध के क्षेत्र में अपने नियमित काम के अलावा, एनसीबी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता फैलाने में भी कुछ काम करता है। इन कार्यक्रमों में शामिल है-

- नुक्कड़ नाटक/सांस्कृतिक कार्यक्रम
- ड्रग के दुरुपयोग के खिलाफ दौड़
- पब, बार और हवाई अड्डे पर जागरूकता बोर्ड का प्रदर्शन
- शपथ ग्रहण समारोह
- प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन
- रेडियो चैनल के माध्यम से ड्रग के खिलाफ संदेश
- ड्रग जागरूकता के बारे में एसएमएस अलर्ट
- जागरूकता पैदा करने के लिए 26 जून को 'ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध ट्रैफिकिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाना।

2022 के दौरान, एनसीबी ने देश के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 574 जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रम चलाए, जिनमें माननीय प्रधान मंत्री के विजन 'नशा मुक्त भारत' को पूरा करने के लिए लगभग 1,50,120 प्रतिभागियों को शामिल किया गया।

> विकसित भारत के लिए आवश्यक है - भारत का सरकारी सिस्टम, हर देशवासी की आकांक्षा को सपोर्ट करें। पहले ये सोच थी कि 'सरकार सब कुछ करेगी', लेकिन अब सोच है कि 'सरकार सबके लिए करेगी' । आज की सरकार का ध्येय है-नेशन फर्स्ट - सिटीजन फर्स्ट; आज की सरकार की प्राथमिकता है - वंचितों को वरीयता'। आज के आकांक्षी नागरिक सिस्टम में बदलाव देखने के लिए लंबे समय तक इंतजार करने को तैयार नहीं हैं।
>
> -श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

विकास और प्रोत्साहन की बहार

» ब्यूरो

विकास के मामले में भारतीयों का कोई जोड़ नहीं है। इसके पीछे नागरिकों की मेहनत के अलावा प्रधानमंत्री के नेतृत्व की अहम भूमिका है। जनता में आम जन से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक आती है। 21 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभा में उपस्थित सिविल सेवा के अधिकारियों को 16 वें सिविल सेवा दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जब समय सीमित होता है तो दिशा और कार्यशैली तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की चुनौती दक्षता को लेकर नहीं है, बल्कि यह पता लगाने की है कि कमियों को कैसे खोजा और दूर किया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको इस कालखंड में देश की सेवा का अवसर मिला है... हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है, हमारे लक्ष्य कठिन हैं लेकिन हौसला कम नहीं है, हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले ही चढ़नी है, लेकिन इरादे आसमान से भी ज्यादा ऊंचे हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है, उसने हमारे देश को बहुत ऊंची छलांग के लिए तैयार कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी-कर्मचारी वही हैं, लेकिन परिणाम बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है, अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है, अगर भारत के विकास को नई गति मिली है, तो ये भी आप जैसे कर्मयोगियों की भूमिका के बिना संभव नहीं था।

प्रधानमंत्री ने सरकारी सेवकों से कहा कि जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। पहला है 'गेटिंग थिंग्स डन'. दूसरा है ' लेटिंग थिंग्स हैपन' पहला एक्टिव एटीट्यूड और दूसरा पैसिव एटीट्यूड का प्रतिबिंब है। पहले तरीके से जीने वाले व्यक्ति की सोच होती है कि हां, बदलाव आ सकता है। दूसरे तरीके में विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है, ठीक है, रहने दो, सब ऐसे ही

पहले ब्यूरोक्रेसी का प्रोत्साहन और उसके कुछ दिन बाद गांव के समग्र विकास की बात। पंचायत स्तर तक केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने का लक्ष्य और उसे प्राप्त करने का पूरा दमखम। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ओर जहां 16वां सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए अधिकारियों को पुरस्कृत किया। 'विकसित भारत– एंपावरिंग सिटीजंस एंड रिचिंग दी लास्ट माइल का विमोचन किया। वहीं, रीवा पहुंचकर ई–ग्राम स्वराज पर बात की। स्वामित्व योजना के तहत भी देश के 35 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए।

चलता है, पहले से भी चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा, वो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा'। 'गेटिंग थिंग्स डन' में यकीन रखने वाले आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं और जब उन्हें टीम में काम करने का अवसर मिलता है, तो वो हर काम का ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवकों के योगदान की लगातार सराहना की है और उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए उत्साहित किया है। यह कार्यक्रम देश भर के सिविल सेवकों को उत्साहित और प्रेरित करने को लेकर प्रधानमंत्री के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में कार्य करता है, ताकि वे विशेष रूप से अमृत काल के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान समान उत्साह के साथ देश की सेवा कर सकें। केंद्र सरकार की नीतियों और अधिकारियों द्वारा उसके सही क्रियान्वयन से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास हो सकता है। जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के अवसर पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने सरकार की उन योजनाओं को विस्तार से बताया, जिसका लाभ गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए 'ई ग्राम स्वराज' और 'जीईएम' पोर्टल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पंचायतों के कामकाज को आसान बनायेंगे। उन्होंने 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड के वितरण तथा मध्य प्रदेश के विकास के लिए रेलवे, आवास, जल और रोजगार से संबंधित 17000 करोड़ की परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गांवों और शहरों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। डिजिटल क्रांति के इस युग में पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। पंचायतों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर का उदाहरण दिया, जिसमें स्थलों के चयन और परियोजना को पूरा करने जैसे मुद्दों को प्रौद्योगिकी की मदद से पूरा किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए जीईएम पोर्टल की सुविधा, पंचायतों द्वारा खरीद को आसान और पारदर्शी बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय कुटीर उद्योग को अपनी बिक्री के लिए एक मजबूत अवसर प्राप्त होगा।

वर्ष 2014 से पहले, पिछली सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की कमी पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि वित्त आयोग ने 70,000 करोड़ रुपये से थोड़ी कम धनराशि ही दी थी, जो देश के पैमाने के अनुसार बहुत अल्प राशि थी, लेकिन 2014 के बाद इस अनुदान को बढ़ा कर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। 2014 के पूर्व के दशक में, मात्र 6000 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया, जबकि वर्तमान सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 30,000 से अधिक पंचायत भवनों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पहले 70 से कम ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं, जबकि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा मिली है।

स्वतंत्रता के बाद पिछली सरकारों द्वारा मौजूदा पंचायती राज व्यवस्था के प्रति विश्वास की कमी को भी रेखांकित किया। 'भारत अपने गांवों में बसता है', महात्मा गांधी के इन शब्दों को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने उनकी विचारधारा पर शायद ही कोई ध्यान दिया, जिसके परिणामस्वरूप पंचायती राज दशकों तक उपेक्षित रहा। आज पंचायतें, भारत के विकास की जीवनशक्ति बनकर सामने आ रही हैं। श्री मोदी ने कहा, 'ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायतों को प्रभावी ढंग से काम करने में मदद कर रही है।'

सरकार की योजनाओं की सम्पूर्णता सुनिश्चित करने की दिशा में लोगों की भागीदारी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री ने 'विकास की ओर साझे कदम' नामक एक अभियान की शुरूआत की। अभियान की थीम, समावेशी विकास है, जिसके तहत अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी सौंपे। इस कार्यक्रम के बाद, देश में स्वामित्व योजना के तहत लगभग 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए, जिनमें यहां वितरित किए गए कार्ड भी शामिल हैं। 'सभी के लिए आवास' के विजन को पूरा करने की दिशा के एक कदम के रूप में, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के 4 लाख से अधिक लाभार्थियों के 'गृह प्रवेश' कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने लगभग 2,300 करोड़ रुपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेल विद्युतीकरण के साथ–साथ विभिन्न दोहरीकरण, आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। ■

जोश और जुनून से मिलेगी सफलता

हर चिंतन शिविर चिंतन से आरंभ होता है, मनन के साथ आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन के साथ समाप्त होता है। पूर्वोत्तर और मणिपुर ने देश में खेल परंपरा को आगे ले जाने में अहम योगदान किया है।

» ब्यूरो

सफलता के लिए जरूरी है कि लगातार कोशिशें की जाएं। निरंतरता बनी रहे। भारत को दुनिया के विकसित देशों में शामिल होकर अपना दमखम दिखाना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि युवाओं को सबसे अधिक तैयार रहना होगा, सशक्त बनना होगा। इस बात को एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने हर्ष व्यक्त किया कि इस वर्ष 'चिंतन शिविर' मणिपुर में हो रहा है और पूर्वोत्तर के अनेक खिलाड़ियों ने देश के लिये पदक जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने सागोल कांगजाई, थांग-ता, यूबी लाकपी, मुकना और हियांग तन्नाबा जैसे देसी खेलों को रेखांकित किया और कहा कि ये सभी खेल अपने आप में काफी आकर्षक खेल हैं। पूर्वोत्तर और मणिपुर ने देश में खेल परंपरा को आगे ले जाने में अहम योगदान किया है। देसी खेलों के सिलसिले में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के ऊ-लवाबी नामक खेल का उल्लेख किया, जो कबड्डी से मिलता-जुलता है। इसी तरह हियांग तन्नाबा से केरल की नौका-दौड़ की याद आती है। उन्होंने पोलो के साथ मणिपुर के ऐतिहासिक जुड़ाव पर भी गौर किया और कहा कि पूर्वोत्तर देश की सांस्कृतिक विविधता में नये रंग भरता है और देश की खेल विविधता को नये आयाम देता है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि देशभर के खेल मंत्रियों को 'चिंतन शिविर' की समाप्ति तक बहुत-कुछ सीखने का अनुभव मिलेगा।

पिछले वर्ष एथलीटों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनके शानदार प्रयासों, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पधाओं में उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए खिलाड़ियों को आगे और सहायता दी जायेगी। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि खेल मंत्रालय और उसके विभाग की तैयारियों की परख स्क्वैश वर्ल्ड कप, हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी और एशियन यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैम्पियनशिप जैसी आगामी प्रतिस्पर्धाओं में होगी। उन्होंने जोर दिया कि जब खिलाड़ी खुद को तैयार कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि सभी खेल मंत्रालय खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक अलग नजरिये के साथ काम करें। फुटबाल और हॉकी में जिस तरह एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी पर नजर रखता है, उसका उल्लेख करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि हर टूनार्मेंट के लिये अलग-अलग रणनीतियां बनाने की जरूरत है तथा हर मैच को मद्देनजर रखते हुये सोचना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 'आपको अल्प-कालीन, मध्य-कालीन और दीर्घ-कालीन लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस तो कोई भी खिलाड़ी अकेले प्राप्त कर सकता है, लेकिन निरंतरता होने से उसके शानदार प्रदर्शन का रास्ता खुल जाता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पधाओं और खेल टूनार्मेंटों में खेलना जरूरी है, ताकि खिलाड़ी इससे खूब सीख सकें। खेल मंत्रियों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी की अनदेखी न होने पाये। पूर्वोत्तर में खेलों में किये जाने वाले विकास को रेखांकित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र राष्ट्र के लिये बड़ा प्रेरणा-स्रोत है। खेल अवसंरचनाओं से जुड़ी 400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनायें आज पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने इम्फाल के राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया, जो आने वाले दिनों में देश के युवाओं को नये अवसर उपलब्ध करायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खेलो इंडिया योजना और टॉप्स जैसे प्रयासों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। पूर्वोत्तर भारत के हर जिले में कम से कम दो खेलो इंडिया केंद्र और हर राज्य में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं। ■

> आपको खेल अवसंरचना और हर टूनार्मेंट के अनुसार खेल प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा; आपको अल्प-कालीन, मध्य-कालीन और दीर्घ-कालीन लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। खेल अवसंरचना से जुड़ी 400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनायें पूर्वोत्तर में विकास को नई दिशा दे रही हैं।
>
> -श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

'गागर में सागर' है 'मन की बात'

हर व्यक्ति की चिंता और प्रत्येक की प्रगति की कामना के साथ प्रधानमंत्री बीते 100 महीने से 'मन की बात' करते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है और लोकतंत्र का एक मुख्य पहलू जनता और नेता के बीच संवाद है। ये संवाद जितना मजबूत और सार्थक होता है लोकतंत्र की नींव उतनी ही मजबूत और सफल होती है।

» ब्यूरो

संवाद और संप्रेषणीयता में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री का दायित्व निभाते हुए भले ही व्यक्तिगत रूप से देश की हर जनता से मिलना संभव नहीं हो पाता हो, लेकिन हर व्यक्ति की चिंता और उनसे बात करने की उत्कंठा ने 'मन की बात' कार्यक्रम की शुरूआत की। यह बात आम लोगों से लेकर खास लोगों ने कही है। आकाशवाणी के माध्यम से साल 2014 से लगातार हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते आ रहे हैं। सौवें संस्करण में देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी खूब चर्चा हुई। 'मन की बात' के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए 'मन की बात' अहम से वयम तक की यात्रा है। 'मन की बात' मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गई है। इसके अलावा लोगों का देश के लिए योगदान सहित कई बातों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद परिस्थितियों की विवशता के कारण उनके पास जनता से कट जाने की चुनौती थी। लेकिन 'मन की बात' ने इसका समाधान दिया और सामान्य लोगों से जुड़ने का रास्ता दिया। यह देशवासियों की अच्छाइयों और उनकी सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वहां आम जन से मिलना-जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था, लेकिन जब वह प्रधानमंत्री बने, तो वह जीवन अलग थी, क्योंकि काम का स्वरूप अलग था, दायित्व अलग थे और साथ ही परिस्थितियों का बंधन व सुरक्षा का तामझाम। उन्होंने कहा, 'ऐसे में मैं खाली-खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क भी मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ हैं, मैं उनसे ही कटकर जी नहीं सकता था। 'मन की बात' ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया। आम लोगों से जुड़ने का रास्ता दिया। इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया।'

इससे पूर्व 26 अप्रैल, 2023 को राजधानी दिल्ली के 'राष्ट्रीय कॉन्क्लेव : मन की बात@100' के समापन समारोह को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित

शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केन्द्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, वित्त राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में जनसंवाद के कई माध्यम होते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' के माध्यम से जनसंवाद के लिए आकाशवाणी को चुना। आकाशवाणी भारत की जनता की आत्मा की आवाज है। बदलते समय और प्रचार के अलग-अलग माध्यमों के कारण आकाशवाणी को लोग लगभग भूल चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' के माध्यम से युवा पीढ़ी को जोड़कर उसे प्रेरित करने का और आकाशवाणी को नया जीवन देने का काम किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी को जनसंवाद का माध्यम बनाया और 6 दशक पुराने जनसंवाद के इस माध्यम को देश के हर गांव और घर तक पहुंचाया। श्री अमित शाह ने कहा कि लगभग 700 से अधिक कंट्रीब्यूटर और 270 संगठनों की हौंसला अफजाई करके मोदी जी ने उन्हें ये प्रेरणा और आत्मविश्वास दिया है कि वे भी समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। 'मन की बात' कार्यक्रम अर्जेंटीना, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, माली, ग्रीस, ओमान, गुयाना और जापान जैसे कई देशों में पहुंचा है और इसने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को भी चरितार्थ किया है। इस कम्युनिकेशन स्किल के 4 प्रमुख स्तंभ हैं- इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और फिज़िकल गतिविधियों को बढ़ावा देना। श्री शाह ने कहा कि ये एक PERFECT कम्युनिकेशन है, जिसका अर्थ है, P- Peace, E-Empowerment, R- Reflective, F- Festive, E- Economical Development, C- Caring और T- Thoughtful.

असल में, इस कार्यक्रम के माध्यम से लद्दाख और लक्षद्वीप से लेकर पूर्वोत्तर और पंजाब तक, किसान से विज्ञान तक, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर स्टार्टअप तक और सहकारिता से स्पेस तक व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ-साथ हर क्षेत्र को 100 एपिसोड्स में छूने का बेहद सफल प्रयास किया है। भारत के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के 2 बड़े योगदान हैं- हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जनता के मत की अभिव्यक्ति को प्रदूषित करने वाले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण से मुक्त करके इसे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले गए हैं। इसने हमारे लोकतंत्र को एक नई आयु, ऊर्जा और दिशा दी है। दूसरा, पद्म पुरस्कारों का लोकतंत्रीकरण किया, जो पहले सिफारिशों से मिलते थे। प्रधानमंत्री लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। 'मन की बात' के माध्यम से समाज के अंदर छोटे छोटे प्रयोग करने वाले, कई क्षेत्रों में योगदान देने वाले, समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाले और समाज को सही दिशा देने वाले कई लोगों और संस्थाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है।

उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर, 2014 से शुरू हुआ 'मन की बात' कार्यक्रम आकाशवाणी के 501 रेडियो स्टेशन, 23 भाषाओं और 29 बोलियों में सुना जाता है।

लोकतंत्र के सुफल तभी मिल सकते हैं, जब नेता और जनता के बीच संवाद हो। ये एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्यक्रम है, जिसमें 9 साल से देश के प्रधानमंत्री जनता से संवाद कर रहे हैं, लेकिन उन्होने एक भी राजनीतिक बात नहीं की है। मोदी जी ने इस कार्यक्रम में देश की सज्जन शक्ति, सात्विक शक्ति और सृजनात्मक शक्ति को प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। जिस देश की ये तीनों शक्तियां संगठित, परिष्कृत और पुरस्कृत ना हों उस देश में लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। मोदी जी ने लोकतंत्र के इस मूलमंत्र को 100 एपिसोड्स के माध्यम से जमीन पर उतारा है।

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

इसके अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी इसका प्रसारण होता है। कई जनजागरण और सामाजिक बदलाव के कामों को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण और जल संचय, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, सुगम्य भारत और सांस्कृतिक विरासत को सफल बनाया है। ये सभी भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाले और सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नवंबर, 2022 के 'मन की बात' के एपिसोड में भारत द्वारा G-20 की अध्यक्षता, विश्व शांति की अपील और वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने रखा है, उसने वसुधैव कुटुंबकम को वैश्विक स्वीकृति दिलाने का काम किया है। इसके अलावा आत्मिक और वैश्विक शांति अद्वैत हैं, 'मन की बात' के जरिए ये बताकर मोदी जी ने हमारे पुराणों के रहस्यों को भी लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही 92वें एपिसोड में पोषण माह मनाने के आह्वान के साथ कुपोषित लोगों की ओर मोदी जी ने समाज का ध्यान आकर्षित किया। स्टार्टअप इंडिया को लेकर फैली गलत धारणा को भी मोदी जी ने 'मन की बात' के जरिए दूर किया और सहकारिता आंदोलन को भी गति देने का काम किया। भारत के कई उत्सवों को 'मन की बात' में शामिल करके एक भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया। 24 सितंबर, 2017 के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा था कि खादी एक वस्त्र नहीं विचार है और इस विचार को महात्मा गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा किसी ने स्वीकृत और प्रचारित किया है तो 'मन की बात' के माध्यम से किया है। ग्रामीण इकोनॉमी को 'मन की बात' के माध्यम से बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलौनों के बारे में बात की और 2018-19 खिलौनों का आयात 371 मिलियन डॉलर से 70% घटकर 2021-22 में 110 मिलियन डॉलर रह गया और भारतीय खिलौनों का निर्यात 202 मिलियन डॉलर से बढ़कर 326 मिलियन डॉलर हो गया। यह बताता है कि 'मन की बात' का कितना सामाजिक सरोकार की ओर कितना बड़ा असर होता है और आज बच्चे भारतीय खिलौनों से खेल रहे हैं। ■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

सबके लिए है 'स्वागत'

स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम के चार घटक हैं : राज्य स्वागत, जिला स्वागत, तालुका स्वागत और ग्राम स्वागत। राज्य स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं जनसुनवाई में शामिल होते हैं। जिला कलेक्टर जिला स्वागत का प्रभारी होता है, जबकि मामलातदार और संवर्ग-1 स्तर का एक अधिकारी तालुका स्वागत का प्रमुख होता है। ग्राम स्वागत में, नागरिक हर महीने की 1 से 10 तारीख तक तलाटी/मंत्री के पास आवेदन दाखिल करते हैं। ये आवेदन निवारण के लिए तालुका स्वागत कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसके अलावा, नागरिकों के लिए एक लोक फरियाद कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें वे स्वागत इकाई में अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं।

» ब्यूरो

'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवन्सेज बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) की शुरूआत अप्रैल 2003 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उस समय की गई थी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस कार्यक्रम की शुरूआत उनके इस विश्वास से प्रेरित थी कि एक मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने राज्य के लोगों की समस्याओं को हल करना है। इस संकल्प व जीवनयापन को आसान बनाने की प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को काफी पहले ही पहचान लेने के साथ, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोदी ने अपनी तरह का पहला तकनीक-आधारित इस शिकायत निवारण कार्यक्रम को शुरू किया था।

27 अप्रैल को इसके बीस वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस समयावधि को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि स्वागत पहल को शुरू करने के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है। इसके माध्यम से नागरिक न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं बल्कि समुदाय के सैकड़ों मुद्दों को भी उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का रवैया मैत्रीपूर्ण होना चाहिए जिससे आम नागरिक आसानी से अपने मुद्दों को सरकार के साथ साझा कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वागत पहल अपने अस्तित्व के 20 वर्ष पूरे कर रही है। उन्होंने लाभार्थियों के साथ बातचीत में अपने पिछले अनुभवों को याद किया। उन्होंने कहा कि यह नागरिकों का प्रयास और समर्पण है जो स्वागत पहल को एक शानदार सफलता दिलाता है और इस दिशा में योगदान देने वाले सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी योजना की नियति उस योजना की नीयत और दूरदर्शिता से तय होती है, जब उसकी कल्पना की जाती है। उन्होंने याद किया कि 2003 में जब यह पहल शुरू की गई

थी तब मुख्यमंत्री के रूप में उनकी आयु अधिक नहीं थी और उन्हें भी इस आम बात का सामना करना पड़ा था कि सत्ता सभी को बदल देती है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट था कि मैं कुर्सी की सीमाओं का गुलाम नहीं बनूंगा और लोगों के बीच रहूंगा और उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। इस दृढ़ संकल्प से प्रौद्योगिकी के प्रयोग (स्वागत) द्वारा जन शिकायतों पर ध्यान देने की प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वागत के अस्तित्व का मूल विचार लोकतांत्रिक संस्थाओं में आम नागरिकों के विचारों का स्वागत करना था, चाहे वह कानून हो या समाधान। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वागत ईज ऑफ लिविंग और रीच ऑफ गवर्नेंस के विचार के साथ खड़ा है।

उन्होंने रेखांकित किया कि गुजरात के सुशासन मॉडल ने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन का उल्लेख किया जिसने ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही के रूप में स्वागत द्वारा सुशासन का प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्वागत पहल की संयुक्त राष्ट्र ने बहुत सराहना की और उसे सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि गुजरात को 2011 में कांग्रेस शासन के दौरान स्वागत पहल की सफलता के कारण ई-गवर्नेंस के लिए भारत सरकार से स्वर्ण पुरस्कार भी मिला था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए यह सबसे बड़ा पुरस्कार है कि हम स्वागत पहल के माध्यम से गुजरात के लोगों की सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि हमने एक व्यावहारिक प्रणाली तैयार की। जन सुनवाई की पहली प्रणाली खंड और तहसील स्तर पर बनाई गई थी। उसके बाद जिला स्तर पर जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं राज्य स्तर पर उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें विभिन्न पहल और योजनाओं के प्रभाव तथा पहुंच एवं इन्हें लागू करने वाली एजेंसियों और अंतिम लाभार्थियों के बीच संबंधों को समझने में बहुत मदद मिली। स्वागत ने नागरिकों को सशक्त बनाया और विश्वसनीयता हासिल की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही स्वागत कार्यक्रम सप्ताह में केवल एक बार आयोजित किया जाता था, लेकिन इससे संबंधित कार्य पूरे महीने किये जाते थे, क्योंकि सैकड़ों शिकायतें थीं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि वह यह समझने के लिए एक विश्लेषण करेंगे कि क्या कोई विशिष्ट विभाग, अधिकारी या क्षेत्र थे जिनकी शिकायतें दूसरों की तुलना में अधिक बार दर्ज की गई थीं। श्री मोदी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर नीतियों में भी संशोधन किया गया, इसका गहन विश्लेषण किया गया, इससे आम नागरिकों में विश्वास की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने टिप्पणी की कि समाज में सुशासन का पैमाना लोक शिकायत निवारण प्रणाली की गुणवत्ता पर निर्भर है और यही लोकतंत्र की सच्ची परीक्षा है।

असल में, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की शिकायतों को त्वरित, कुशल और

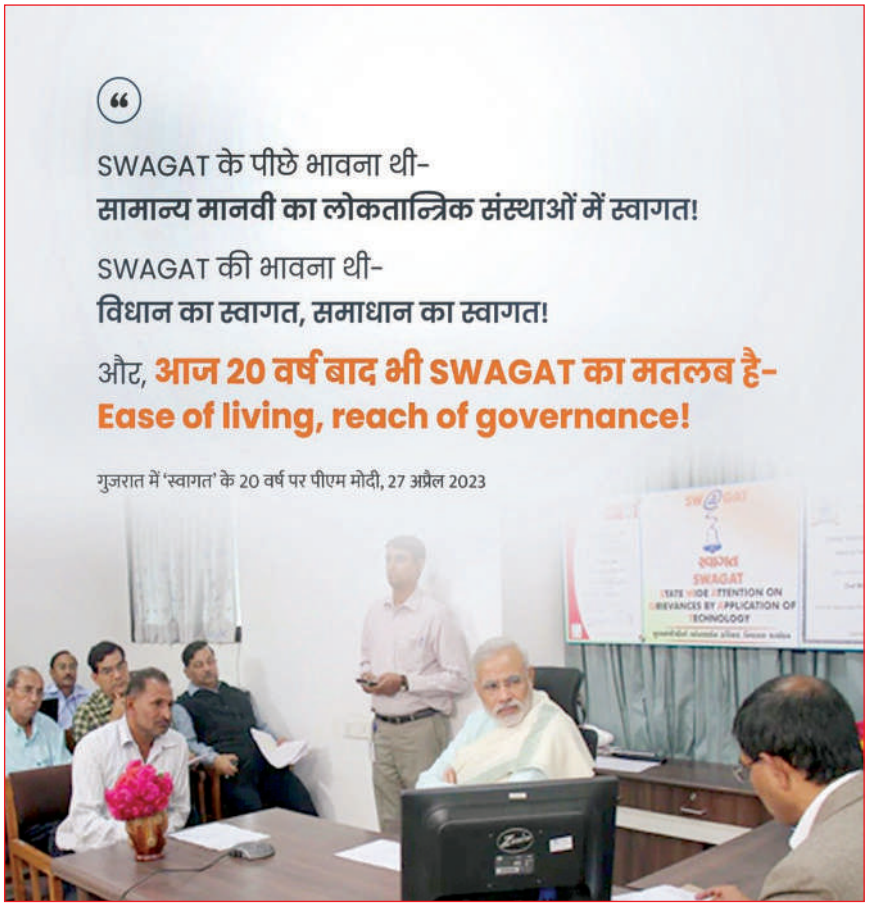

समयबद्ध तरीके से हल करके उनके और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना था। समय के साथ, स्वागत ने लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव डाला और यह कागजरहित, पारदर्शी एवं बाधा-मुक्त तरीके से समस्याओं को हल करने का एक प्रभावी उपकरण बन गया।

स्वागत की विशिष्टता यह है कि यह आम आदमी को अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद करता है। यह हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित किया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री शिकायत निवारण के लिए नागरिकों के साथ बातचीत करते हैं। यह शिकायतों के त्वरित समाधान के जरिए आम लोगों और सरकार के बीच की खाई को पाटने में सहायक रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक आवेदक को निर्णय के बारे में सूचित किया जाए। सभी आवेदनों की कार्यवाही ऑनलाइन उपलब्ध होती है। अब तक दर्ज की गई 99 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

स्वागत ने सरकार में बनी बनाई लकीरों पर चलने की पुरानी धारणा को बदल दिया। उन्होंने कहा, 'हमने यह साबित किया कि शासन पुराने नियमों और कानूनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शासन होता है नवाचारों और नए विचारों से।' श्री मोदी ने याद दिलाया कि 2003 में उस समय की सरकारों द्वारा ई-गवर्नेंस को बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं दी गई थी। कागजी कार्रवाइयों और वास्तविक फाइलों के कारण बहुत देरी तथा परेशानी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं थी। इन परिस्थितियों में, गुजरात ने भविष्यवादी विचारों पर काम किया। और आज स्वागत जैसी व्यवस्था शासन के अनेक समाधानों की प्रेरणा बन गई है। कई राज्य इस तरह की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। केन्द्र में हमने सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए प्रगति नाम का एक सिस्टम भी बनाया है। प्रगति ने पिछले 9 वर्षों में देश के तेज विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। यह अवधारणा भी स्वागत के विचार पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रगति के माध्यम से लगभग 16 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की है और इससे कई परियोजनाओं में तेजी आयी है।

अपने संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने एक बीज के अंकुरित होकर सैकड़ों शाखाओं वाले एक विशाल वृक्ष में विकसित होने की उपमा दी और यह विश्वास व्यक्त किया कि स्वागत का विचार शासन में हजारों नए नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शासन संबंधी पहल को इस तरह मनाया जा रहा है क्योंकि यह उनमें नई जान और ऊर्जा का संचार करती है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह जन-उन्मुख शासन का एक मॉडल बनकर जनता की सेवा करना जारी रखेगा। ■

असम-अरुणाचल में समझौते से हुआ समाधान

मोदी सरकार के प्रयासों से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चला आ रहा अंतरराज्यीय सीमा विवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये अहम समझौता सहकारी संघवाद का एक सफल उदाहरण है और ये अन्य राज्यों के बीच सीमा विवादों के समाधान के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगा ।

» ब्यूरो

जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सशक्त सरकार से समाज और राज्य का विकास होगा, तो इसे व्यापक रूप में जनसमर्थन मिलता रहा है। कई पुरानी समस्याओं के समाधान में सरकार कारगर साबित हुई है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद रहा है। बातचीत का दौर चला, लेकिन यह निर्णायक स्तर पर पहुंचा 20 अप्रैल, 2023 को। यह दिन पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ऐतिहासिक बन गया। इस समझौते के तहत 700 किलोमीटर से अधिक की असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा के संबंध में निर्णय पूर्ण और अंतिम होगा। कहा गया कि दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गांव से संबंधित कोई नया दावा पेश नहीं किया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा से सटे 123 गांवों से संबंधित इस विवाद की समाप्ति के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, प्रशासनिक सुविधा, सीमा से निकटता और निवासियों की आकांक्षाओं को

ध्यान में रखते हुए समझौता किया गया है। समझौते के बाद सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दोनों राज्यों की सीमाओं के सटीक निर्धारण के लिए दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।

यह समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित, शांत और विवादरहित पूर्वोत्तर के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से बीते कुछ वर्षों से पूर्वोत्तर के हर क्षेत्र में चौतरफा विकास हो रहा है। ये समझौता दोनों राज्यों सहित पूरे पूर्वोत्तर के लिए शुभ साबित होगा और विकास के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर गए हैं और हमेशा वहां की भाषा, संस्कृति, साहित्य, वेशभूषा, खान-पान को बढ़ावा दिया है। हाल ही में असम में बिहू उत्सव के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले स्थानीय बिहू नृत्य का साक्षी बनकर प्रधानमंत्री ने इसे विश्वप्रसिद्ध बनाने का काम किया है।

उल्लेखनीय है कि 20 अप्रैल को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच वर्षों से लंबित अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस महत्वपूर्ण समझौते पर असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला भी उपस्थित थे।

बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश 804.1 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और अरुणाचल प्रदेश को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच यह सीमा विवाद चल रहा था। 15 जुलाई, 2022 को 'नामसाई घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर के दौरान निकले 27 गांवों के समाधान और आज के समझौते के तहत निकले 34 गांवों के समाधान शामिल हैं। इन 71 गांवों में से अरुणाचल प्रदेश में से एक गांव को असम में शामिल किया जाएगा, 10 गांव असम में ही बने रहेंगे और 60 गांवों को असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में शामिल किया जाएगा। बाकि बचे 52 गांवों में से 49 गांवों की सीमाएं अगले छह महीनों में क्षेत्रीय समितियों द्वारा तय की जाएंगी, वहीं भारतीय वायुसेना के बमबारी क्षेत्र में आने वाले तीन गांवों का पुनर्वास किया जाना है। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों की सरकारें सहमत हुई हैं कि 123 गांवों पर यह अंतिम फैसला होगा और यह विवाद समाप्त हुआ।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे समय में जबकि देश स्वतंत्रता का 75वां साल मना रहा है, दोनों राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित 123 गांवों का विवाद अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश की ओर से पुराने लंबित सीमा विवाद को 'सौहार्दपूर्ण' तरीके से सुलझाया जाना दोनों राज्यों के लिए 'ऐतिहासिक' घटना है। 1972 से जारी इस पुराने सीमा विवाद की समाप्ति पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वांगिण विकास

सुरक्षा के साथ 'अर्थ' भी

» ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महत्व को साझा करते हुए कहा कि भारत बहुआयामी राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक विषयों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के विभागों के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि यह संगठन आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत के कारण जी 20 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक कार्य समूह का गठन किया गया। गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी। भारत ने सार्क, बिम्सटेक और एससीओ देशों के साथ संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास की मेजबानी की है। एससीओ शायद दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो वैश्विक आबादी का 40 प्रतिशत, वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत और दुनिया के कुल भूमि का 22 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत आपदा जोखिम में कमी को विशेष महत्व देता है। भारत अपनी विशेषज्ञता और अनुभव एससीओ सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास के लिए साझा करने को तैयार है। भारत का मानना है कि कोई भी हादसा बड़ा या छोटा नहीं होता। देश ने सूखे, बाढ़, गर्मी, शीत लहर, चक्रवात की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार देखे हैं। भारत ने अब पहले से अधिक सटीक और समय पर पूर्व चेतावनी देने वाली तकनीक को विकसित कर लिया है। 2018 में किंगदाओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए SECURE थीम को आगे बढ़ाना एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकता है। SECURE का मतलब बताते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि S- सुरक्षा, E- आर्थिक सहयोग, C- कनेक्टिविटी, U- एकता, R- संप्रभुता और अखंडता का सम्मान और E- पर्यावरण संरक्षण है।

भारत के नेतृत्व वाले सीडीआरआई में आज दुनिया भर के 39 सदस्य हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में अनेक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। भारत के नेतृत्व वाले Coalition For Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) में दुनियाभर से 39 सदस्य जुड़ चुके हैं। CDRI ने सदस्य देशों के साथ यह साझा प्रयास किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सारे निवेश इस प्रकार किए जाएं जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर Disaster Resilient हो। इसके अलावा CDRI द्वारा Small Island Developing States, जैसे विश्व के सर्वाधिक आपदा संभावित क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इन विचार-विमर्शों के आधार पर, सदस्य-राज्यों ने तैयारी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया और आपातकालीन प्रतिक्रिया और संयुक्त रूप से एससीओ के ढांचे के भीतर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को कम किया। प्रतिभागियों ने 2023-2025 में आपातकालीन स्थिति के उन्मूलन में सहायता प्रदान करने में सहयोग पर एससीओ सदस्य-राज्यों के बीच समझौते के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर भी चर्चा की और उसे मंजूरी दी। कार्य योजना एससीओ सदस्य-राज्यों के बीच आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन से निपटने में सहयोग बढ़ाने में योगदान देती है। ■

विजन 2047 : एक्शन प्लान तैयार

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 18 अप्रैल, 2023 को गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के 'चिंतन शिविर' की अध्यक्षता की। चिंतन शिविर का उद्देश्य गृह मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करना तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'विजन 2047' को लागू करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना था। श्री शाह ने MHA Dashboard, Government Land Information System (GLIS), Budget Utilization, E-Office और Special Recruitment Drive आदि कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा आने वाले वर्षों में अपनी प्राथमिकताओं और डिलिवरेबल्स पर किए गये कार्यों और आत्मनिर्भर भारत, विभिन्न बजट घोषणाओं तथा महत्वपूर्ण लंबित मुद्दों पर उनकी स्थिति की भी समीक्षा की।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने साइबर अपराध प्रबंधन, पुलिसबलों के आधुनिकीकरण, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में IT के बढ़ते उपयोग, लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट और तटीय सुरक्षा मुद्दों आदि हेतु एक इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। श्री शाह ने अपराधों के क्रिटिकल एनालिसिस के लिए CCTNS डेटाबेस का विस्तृत उपयोग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल दिया, जिससे महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने CAPF कर्मियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कदमों जैसे उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और हाऊसिंग सेटिस्फेक्शन रेश्यों में सुधार उठाने पर भी जोर दिया। गृह मंत्री ने प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के सभी विभागों को नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों को विकास योजनाओं की निगरानी के लिए नियमित दौरे करने चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।

और शांति लेकर आएगी।

श्री अमित शाह ने काफी समय से लंबित इस सीमा विवाद को सुलझाने में असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों ने विवाद के निपटारे के लिए क्षेत्रीय समिति बनाई, आम लोगों से बात की और सभी को इस प्रयास में समाहित करने का काम किया है।

मोदी सरकार के प्रयासों से आज पूरे पूर्वोत्तर में हर क्षेत्र में चौतरफा विकास होता दिख रहा है और ये पूरा क्षेत्र प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार की ओर से दोनों राज्यों की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये समझौता दोनों राज्यों के लिए शुभांकर साबित होगा और विकास के नए द्वार खोलेगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि बीते आठ वर्षों में केंद्र सरकार ने किस प्रकार प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र की समस्याओं को देखा और उसके समाधान के लिए त्वरित गति से कार्रवाई की। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2018 से भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना और हिंसा खत्म करने के लिए ब्रू एनएलएफटी (NLFT), कार्बी आंगलोंग, आदिवासी शांति समझौते किए हैं। इन समझौतों के परिणामस्वरूप पूरे पूर्वोत्तर में शांति की एक नई पहल शुरू हुई है और अब तक 8000 से अधिक हथियारबंद युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। 2014 की तुलना में उत्तरपूर्व में हिंसा की घटनाओं में 67 प्रतिशत, सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या में 60 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु की संख्या में 83 प्रतिशत की कमी आई है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के कई स्थानों से AFSPA को हटा लिया है। असम में 70 प्रतिशत, मणिपुर के 6 ज़िलों के 15 पुलिस स्टेशन, अरुणाचल में 3 ज़िले छोड़कर सभी ज़िले, नगालैंड में 7 ज़िले और त्रिपुरा व मेघालय पूर्णतया AFSPA से मुक्त हो चुके हैं।

असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने समझौते पर हस्ताक्षर को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह शांति और समृद्धि लाने वाला बनेगा। 51 साल के बाद, भारत का सबसे पुराना अंतरराज्यीय सीमा विवाद अपने नतीजे पर पहुंच गया है और यह प्रधानमंत्री के आशीर्वाद, केंद्रीय गृहमंत्री के दिशा-निर्देश और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के अथक सहयोग से संभव हुआ है। इससे पूर्वोत्तर में भाईचारे की भावना बढ़ेगी और हमारा संघीय ढांचा मजबूत होगा, क्योंकि यह राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने का नया तरीका लाया है।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने सीमा विवाद की समाप्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया और भरोसा जताया कि इससे दोनों राज्यों में शांति और विकास में बड़ा बदलाव आएगा। यह समझौता प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की प्रेरणा और राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा असम सरकार के सक्रिय सहयोग से संभव हो सका है। अरुणाचल प्रदेश की ओर से स्थानीय आयोग के समक्ष 2007 में जिन 123 गांवों पर दावा किया गया था, उनमें से 71 पर सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल आया है। ■

बेहतर समन्वय के साथ सुरक्षा और समृद्धि के काम पर भारत सरकार के गृह सचिव लगातार सक्रिय रहते हैं। हर बैठक को सार्थक बिंदु तक पहुचांने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में कई बैठकों से यही स्वर निकल रहा है।

सुरक्षा के साथ विकास

» ब्यूरो

प्रधानमंत्री की ओर से विजन 2047 का मंत्र दिया गया है। इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के दिशा-निर्देशन में केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला लगातार इसे पूरा करने के लिए विभागीय बैठकों में तत्पर रहते हैं। 12 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित 5वें भारत-यूके गृह मामलों के संवाद में केंद्रीय गृह सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक में सर मैथ्यू रायक्रॉफ्ट की अगुवाई में ब्रिटेन प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने चल रहे सहयोग की समीक्षा की और यूके में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, मादक पदार्थों की तस्करी, प्रवासन, प्रत्यर्पण, भारत विरोधी गतिविधियों में सहयोग को आगे बढ़ाने में अवसरों और तालमेल का पता लगाने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की पहचान की। इसमें खालिस्तान समर्थक उग्रवाद भी शामिल है।

भारतीय पक्ष ने विशेष रूप से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा यूके की शरण स्थिति के दुरुपयोग पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया और यूके के साथ बेहतर सहयोग और यूके आधारित खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों की निगरानी बढ़ाने और उचित सक्रिय कार्रवाई करने का अनुरोध किया। भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में सेंध को लेकर भारत की चिंताओं पर भी जोर दिया गया।

बैठक का समापन दोनों पक्षों द्वारा जारी साझेदारी पर संतोष व्यक्त करने और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की गति को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त करने के साथ हुआ। इससे पहले 10 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के साथ थे, जिन्होंने 10 अप्रैल, 2023 को अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव किबिथू में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' का शुभारंभ किया था। 12 अप्रैल को, केंद्रीय गृह सचिव ने जम्मू-कश्मीर में रेलवे पटरियों, स्टेशनों या प्रतिष्ठानों के सुरक्षा मूल्यांकन की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में रेलवे, जम्मू-कश्मीर पुलिस, गृह मंत्रालय और अन्य हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। गृह सचिव ने इच्छा व्यक्त की कि प्राथमिकता के आधार पर रेलवे स्टेशनों और जम्मू-कश्मीर की संबंधित स्थापनाओं के सुरक्षा तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सकती है।

केंद्रीय गृह सचिव ने 14 अप्रैल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पर्यटन और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में टैटू ग्राउंड में स्थित रक्षा भूमि को गृह मंत्रालय को हस्तांतरित करने की प्रगति की समीक्षा की।

19 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में मिलेट्स के उपयोग को लेकर बात की। संबंधित संगठनों और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेट्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए कहा।

इसी तरह, 24 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव ने गृह मंत्रालय में आपातकालीन प्रतिक्रिया (आईसीआर-ईआर) परियोजना के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए एससी-एनईसी की बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा, केंद्रीय गृह सचिव ने उसी दिन पैन इंडिया ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (बीबी-पीपीडीआर) संचार नेटवर्क के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव (दूरसंचार) के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्रालय, डीसीपीडब्ल्यू और दूरसंचार विभाग के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्रीय गृह सचिव ने 25 अप्रैल को भारत में एक स्थायी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए एक बैठक की। बैठक में विदेश मंत्रालय, एनआईए, गृह मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, उसी दिन केंद्रीय गृह सचिव द्वारा प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ कदाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिकूल वित्तीय गतिविधियों के संबंध में तीसरी समन्वय बैठक आयोजित की गई थी।

नियामक तंत्र में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह सचिव ने 25 अप्रैल को एक बैठक की, जिसमें साइबर सुरक्षा के हर पहलु पर विस्तार से बात हुई। इसके साथ ही एनआईसी ईमेल सेवाओं को मजबूत करने पर चर्चा की गई। ■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने में है। सीमावर्ती गांवों को 'अंतिम' के बजाय 'प्रथम' गांव कहकर प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज का सूत्र दिया। इसे साधते हुए सरकार एक्शन मोड में है। इसमें आईटीबीपी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। सीमा सुरक्षा, सामाजिक सरोकार और रोजगार की त्रिवेणी के साथ नई पटकथा लिखी जा रही है।

वाइब्रेंट विलेजेज

सीमावर्ती गांवों के विकास से सुरक्षित होता भारत

» ब्यूरो

सोच बदलने से कार्यप्रणाली बदल जाती है। सकारात्मक परिणाम आते हैं। कई समस्याओं का अपने आप निदान होते दिखने लगता है। भारत सरकार ने जब से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, उसके बाद से सीमावर्ती गांवों में विकास की गति तेज हो गई है। सीमांत गांवों में रहने वाले लोग पहले से अधिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। सामाजिक सुरक्षा के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। विकास, संपर्क और सुरक्षा–इस प्रोग्राम का खास मकसद है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस परियोजना से सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी। लोगों

का पलायन रुकेगा और लोग अपने मूल स्थानों में ही रहने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे सीमा की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत की चीन और नेपाल सीमा पर सटे गांवों को सशक्त करने के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसे सीमांत गांवों में सभी जरूरी सुविधाएं जुटाना है। पानी, बिजली, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना है। गांवों में रोजगार और आजीविका के संसाधन उपलब्ध हों, इसके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। यह 4800 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। इसके तहत देश के बॉर्डर लाइन से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों की पहचान की गई है। इसका मकसद LAC से लगे गांवों में सुरक्षा को चुस्त-दुरुस्त करना है। ये गांव अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की उत्तरी सीमा से सटे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। अन्य राज्यों में देखें, तो हिमाचल प्रदेश के 75, लद्दाख (यूटी) के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 गांव इसमें शामिल हैं।

साल 2022-23 से शुरू हुए इस प्रोग्राम को 2025-26 के बीच पूरा करने का लक्ष्य है। इसका एक खास मकसद चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से भारत-तिब्बत सीमा की रक्षा करना भी है। इसके लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की सात बटालियन, 47 नई चौकियों और 12 स्टेजिंग कैंपों को डेवलप करने के लिए 1800 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अपने दौरे पर इस प्रोग्राम के तहत कई परियोजनाओं की शुरुआत की। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी एंजॉ जिले (Anjaw district) में भारत-चीन सीमा पर स्थित 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (Vibrant Villages Programme) को किबिथू गांव में लॉन्च किया गया है। किबिथू में 'स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम' के तहत नौ सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। किबिथू में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि थलसेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के पराक्रम ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी भारत की एक इंच भूमि तक का अतिक्रमण नहीं कर सकता। 1962 में, जो कोई भी इस भूमि का अतिक्रमण करने आया, उसे यहां रहने वाले देशभक्त लोगों के कारण लौटना पड़ा। पहले, सीमावर्ती इलाकों से लौटने वाले कहा करते थे कि वे भारत के अंतिम गांव में गये, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदल दिया और अब लोग कहते हैं कि उन्होंने भारत के प्रथम गांव की यात्रा की। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी नमस्ते नहीं बोलता, क्योंकि लोग एक-दूसरे का अभिवादन 'जय हिंद' के साथ करते हैं, जो हमारे दिलों को देशभक्ति की भावना से भर देता है।

गौर करने योग्य यह भी है कि 'शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठापूर्ण' के मूलमंत्र के साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 9,000 से 18,700 फीट की ऊंचाई के बीच घटते-बढ़ते 3,488 किलोमीटर लंबे पर्वत क्षेत्र, शून्य से भी 45 डिग्री नीचे के पारे में कंपकंपाती ठंडी जगहों, अथाह घाटियों, दुर्गम गड्ढों, नदियों, खतरनाक ग्लेशियरों, पथरीली ढालों और अदृश्य प्राकृतिक खतरों के बीच आईटीबीपी के जवान और अधिकारी लगातार देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात रहते

अधिकारियों और मंत्रियों को वाइब्रेंट विलेज में रहने का आग्रह

सूरजकुंड में हुए दो दिवसीय चिंतन शिविर में स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बॉर्डर और कोस्टल एरिया में हमें विकास की ओर देखना होगा। बजट में भी वाइब्रेंट विलेज की बात कही गई है आपको इस पर सोचना चाहिए। आपके टॉप अफसरों को बार्डर विलेज में नाइट स्टे करने का आग्रह कीजिए। मैं तो मंत्रियों से भी कहूंगा कि 1 साल में कम से कम पांच या सात बार बॉर्डर विलेज में जा कर 2-3 घंटे बिता कर आएं। चाहे वो किसी स्टेट का बॉर्डर विलेज हो या इंटरनेशनल बॉर्डर विलेज हो, आपको बहुत कुछ बारीकियों का पता चलेगा।

फ़ौलादी इरादे

चीन की सीमा से लगी देश की हजारों किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा का दायित्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) निभा रहा है। तापमान भले ही माइनस 45 डिग्री हो, लेकिन इन जवानों-अधिकारियों का जोश हमेशा हिमालय की चोटी की तरह हाई रहता है। सीमा की सुरक्षा के साथ ही वाइब्रेंट विलेज की सोच, सामाजिक सरोकार के साथ रोजगार के नए अवसर भी तैयार करेगी। सात नई बटालियनों के सृजन के साथ आईटीबीपी के सरोकार पहले से अधिक व्यापक होंगे।

हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति ही सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की पहाड़ी सीमाओं के अलावा ये अन्य आपदा के समय लोगों की सेवा करते हैं।

बीते कुछ वर्षों में चीन से लगी सीमा पर कई घटनाएं हुई हैं। आईटीबीपी के जवानों-अधिकारियों ने अपने साहस से दुश्मन का मुकाबला किया। चीन सीमा के उस पार अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। अपने सुरक्षा घेरे को पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आईटीबीपी की आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत करना आवश्यक हो गया है। फरवरी, 2023 में एक कैबिनेट बैठक में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 7 नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी गई है।

इससे अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 9,400 कर्मियों की भर्ती होगी, जहां 47 नई सीमा चौकियां और 12 स्टेजिंग कैंप निर्माणाधीन हैं। इन चौकियों के निर्माण की अनुमति जनवरी, 2020 में ही मिल गई थी। वर्तमान में 3,488 किलोमीटर लंबी चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 176 चौकियां हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए एक सेक्टर मुख्यालय की भी घोषणा की गई। बीते छह दशकों से भारत की चीन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा खासकर तिब्बत क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने काम को बखूबी निभाती आ रही है। कैबिनेट की बैठक में चीन की सीमा से लगे गांवों से पलायन को रोकने और पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया गया।

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी साझा करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बटालियन बनाने का निर्णय लिया गया है। बटालियनों की संख्या में वृद्धि और सेक्टर मुख्यालय की स्थापना का काम वर्ष 2025-26 तक पूरा कर लिया जाएगा। नई बटालियनों के लिए शासकीय एवं आवासीय भवनों के निर्माण, भूमि अधिग्रहण, शस्त्र एवं गोला बारूद के लिए 1808.15 करोड़ अनावर्ती व्यय स्वीकृत किया गया है। कर्मियों के वेतन और राशन के लिए प्रति वर्ष 963.68 करोड़ रुपये के आवर्ती व्यय को मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यह निर्णय भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बल संख्या को वर्तमान 88,000 से बढ़ाकर 97,000 कर देगा। इसके बाद यह देश का चौथा सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे सीमावर्ती गांवों से लोगों का पलायन रुकेगा और वहां सतर्कता का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईटीबीपी की सतर्कता से सीमांत क्षेत्र के गांवों में लोगों में सुरक्षा का भाव पहले से अधिक हुआ है। नई बटालियनों के गठन से इसमें और वृद्धि होगी।

केंद्र सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रत्यक्ष रोजगार के लिए आईटीबीपी के 9400 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परोक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। इसके साथ ही लद्दाख में बन रही ऑल वेदर सड़क के लिए शिनकुन ला टनल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त आईटीबीपी सामाजिक सुरक्षा का दायित्व भी सीमाई क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ ही सिविक एक्शन प्रोग्राम का संचालन करता रहा है।

आईटीबीपी के जवानों ने विभिन्न खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण में इसने अपनी मिसाल स्थापित की है। एवरेस्ट (5 बार) और कंचनजंघा की चोटियों सहित इस बल ने 165 से भी अधिक विश्व स्तरीय चोटियों पर तिरंगा लहराया है। भारत के सर्वोच्च शिखर नंदा देवी, हिमालय में माउंट कामेत और ईरान तथा अमेरिका की पर्वत चोटियां भी इस सूची में शामिल हैं। आईटीबीपी समय-समय पर स्वास्थ्य और जागरूकता शिविर आदि आयोजित करता रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों के लिए आईटीबीपी की ओर से स्वास्थ्य शिविर तो लगाए ही जाते हैं, उन क्षेत्रों में पालतु पशुओं के लिए भी हेल्थ कैंपों का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। सभी को विश्वास में लेकर उनके समेकित विकास के लिए आईटीबीपी लगातार काम कर रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी की 17वीं बटालियन ने ऐसे ही एक कैंप का आयोजन किया जिसमें ग्रामीणों ने अपने पालतू पशुओं की जांच करवाई। आईटीबीपी के ये प्रयास उसे स्थानीय लोगों के साथ जोड़ने में सहायक साबित होते हैं, जिसका प्रभाव अंतत: पुलिस बल के प्रदर्शन में दिखता है। ■

विकास के साथ विरासत की भी बात

•विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराएगा यह अभियान
•पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा और रोजगार के बढ़ेंगे साधन

» ब्यूरो

भारत में कुल 6 लाख 40 हजार गांव है। हर गांव की महक निराली होती हैं। हर गांव, दूसरे गांव से अलग है। हर गांव की भाषा, संस्कृति, जायका, गीत-संगीत, हस्तशिल्प, प्रकृति-सौंदर्य आदि में विविधता है। यह महक बड़े शहर, बड़े राज्य में रहकर नहीं मिल सकती। इस सौंधी महक को जीने और महसूस करने के लिए गांवों में आना होगा। भले ही इसकी छाप हस्तशिल्प और जायके के सफर के माध्यम से ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन महसूस करने के लिए गांवों में रहना होगा, यहां आना होगा। यह आग्रह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी से, विशेषकर भारत के युवाओं से किया। खासतौर से सीमावर्ती गांवों में जाने का आग्रह किया है। यहां आने से आपकी सोच, समझ में विकास होगा। गांवों में रहने वालों का भी भला होगा। आप यहां आएंगे तो खाने से लेकर रहने की व्यवस्था गांव में ही होगी। इसके लिए जो पैसा देंगे, उससे गांव वाले का उद्धार होगा। आने-जाने का यही क्रम जारी रहा तो इससे गांव में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नतीजतन सरकारी खजाने के साथ-साथ गांव भी समृद्ध होंगे।

असल में, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार 4800 करोड़ रुपए खर्च करके चीन सीमा से सटे गांवों का विकास सुनिश्चित करेगा। इसके तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बार्डर से नजदीकी गांवों को चिन्हित किया गया है।

इस बजट में से 2500 करोड़ रुपए से इन सभी गांवों की रोड कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, इस प्रोग्राम से सीमावर्ती गांव की तस्वीर ही बदल जाएगी जब गांवों में इलेक्ट्रिसिटी, पर्यटक केंद्र, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल की सुविधा, सड़क निर्माण, मोबाइल तथा इंटरनेट की सुविधा का विकास होगा तो फिर यहां से पलायन नहीं होगा। जब यहीं रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, तो गांव से पलायन का सवाल ही नहीं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने युवाओं से खास आग्रह किया है, आखिर युवा ही देश का भविष्य हैं। केंद्र सरकार की यह पहल देश और हर नागरिक को मजबूत करेगी।

आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत महोत्सव के ट्वीटर हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक ओडिशा के युवा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किबिथू और तूतिंग गांवों के दौरे पर हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम युवाओं को इस पूर्वोत्तर क्षेत्र की जीवनशैली, जनजातियों, लोक-संगीत और हस्तशिल्प के बारे में जानने तथा इसके स्थानीय जायके और प्राकृतिक सुंदरता में खुद को तल्लीन करने का अवसर दे रहा है।

अमृत महोत्सव के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, एक यादगार अनुभव रहा होगा। मैं दूसरों से, विशेष रूप से भारत के युवाओं से सीमावर्ती गांवों का दौरा करने का आग्रह करूंगा। यह हमारे युवाओं को विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराएगा और उन्हें वहां रहने वालों के आतिथ्य का अनुभव करने का अवसर देगा।

दरअसल, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का आगाज किया। अमृत महोत्सव के ट्विटर हैंडल ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सांस्कृतिक और पारंपरिक आदान-प्रदान को गले लगाने, हमारे दूरदराज के सीमावर्ती गांवों की विविधता का जश्न मनाने और उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने का एक शानदार तरीका है। इस पहल के तहत आजकल ओडिशा के युवा किबिथू और तूतिंग गांवों के दौरे पर हैं।

खास बात यह भी है कि 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' के तहत इन खास इलाकों में विकास केंद्र विकसित करने, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन देकर पर्यटन क्षमता को मजबूत बनाने और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एनजीओ के माध्यम से 'एक गांव एक उत्पाद' की अवधारणा पर स्थायी इको-एग्री बिजनेस के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे एक ओर जहां विकास की गंगा बहेगी, वहीं इन गांवों की विरासत को लोग जान सकेंगे। विरासत के धरातल पर जब विकास की गंगा बहेगी तो बात दूर तलक जाएगी। ■

शहीदों को किया नमन जवानों का उत्साहवर्धन

अरुणाचल प्रदेश दौरे के दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को याद करते हुए कहा कि 2014 से पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। लेकिन पिछले 9 सालों में मोदी जी की लुक ईस्ट नीति के कारण नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास में योगदान देने वाले क्षेत्र में रूप में जाना जाता है।

श्री शाह ने कहा कि एक जमाने में दिल्ली में बैठे नेताओं के गलत दृष्टिकोण के कारण ये क्षेत्र विवादित था, उग्रवाद से ग्रस्त था और यहां शांति, विकास और कनेक्टिविटी का अभाव था। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज यहां विवाद और उग्रवाद समाप्त हो रहे हैं और विकास और शांति के नए युग की शुरूआत हो रही है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरपूर्व में 3 स्तरों पर काम किया है– यहां की अभूतपूर्व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया, विवादों का निपटारा करके शांति स्थापित की, और उग्रवादी समूहों के साथ कई समझौते किए जिनसे 2014 के मुकाबले 2022 में हिंसा में 67 प्रतिशत, सुरक्षाबलों की मृत्यु में 60 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 83 प्रतिशत की कमी आई है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने ब्रू, एनएलएफटी, बोडो, कार्बी–आंगलोंग समझौते किए और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद सुलझाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 70 प्रतिशत नॉर्थईस्ट में से AFSPA को हटा लिया है और वो दिन दूर नहीं है जब पूरे नॉर्थईस्ट से इसे हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वाले युवा आज मेनस्ट्रीम में आकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री अमित शाह ने अपने दौर के दौरान सीमा पर तैनात जवानों का उत्साह वर्धन भी किया। श्री शाह ने कहा कि 1962 की लड़ाई में तत्कालीन कुमाऊं रेजीमेंट ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश निश्चिंत होकर सोता है इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी और सेना के जवानों का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है और उन्हीं के कारण कोई हमारी सीमा की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। श्री शाह ने कहा कि 13 हजार फीट की ऊंचाई पर अपने परिवारों से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य, उत्साह और देशभक्ति प्रणाम योग्य हैं। ■

सीमावर्ती क्षेत्र का सर्वांगीण विकास

रंजीत कुमार पंचनंदा

समय के साथ जब सकारात्मक परिवर्तन होता है, तो लोगों को बेहद खुशी होती है। पहले उत्तराखंड के माणा गांव को देश का सबसे अंतिम गांव कहा जाता था, अब वह देश का पहला गांव हो गया है। यह सकारात्मक सोच है। इससे माणा के लोगों में नया उत्साह आया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस देश के कई सीमावर्ती गांवों के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हमने भी हजारों ग्रामीणों को करीब से जाना और समझा है। वर्तमान सरकार जिस प्रकार से सीमावर्ती गांवों को पहले से अधिक सशक्त कर रही है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए।

देश की सीमाओं को और सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार लगातार बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन गांवों को 'वाइब्रेंट विलेज' का नाम दिया है। कुछ दिनों पहले जिसे अंतिम गांव कहा जाता रहा है उसे प्रधानमंत्री की पहल पर अब देश का पहला गांव कहा जाने लगा है। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज के तहत कई योजनाओं का उद्घाटन किया था। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों और अधिकारियों का भी हौसला अफजाई किया।

देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इससे एक ओर ग्रामीणों के लिए सहूलियत होगी, तो दूसरी ओर आवागमन की सुविधा पहले से अधिक सुलभ होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में जब अच्छी सड़कें बन जाएंगी, तो दूसरे देशों से लगने वाली हमारे सीमाओं पर सुरक्षा बलों का मूवमेंट अधिक हो जाएगा। हमारी सीमाओं की ओर किसी की बुरी नजर नहीं उठेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में इन सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस करती आई है।

आईटीबीपी में तैनात पदाधिकारियों को प्राथमिक प्रशिक्षण से ही प्रतिकूल मौसम में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपना कर्तव्य दृढता के साथ करने हेतु विशेष रूप से तैयार किया जाता है। प्राथमिक प्रशिक्षण के उपरान्त कर्मियों को आईटीबीपी के विविध प्रशिक्षण संस्थानों में Mountain warfare पर्वतारोहण, Ice Craft तथा High Altitude एवं बर्फीले इलाकों में विषम परिस्थितियों में खुद को रखने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्तमान केंद्र सरकार का यह बेहद अहम निर्णय रहा कि भारत-चीन सीमा के सामरिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा आईटीबीपी की 07 नई बटालियन एवं 01 क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गई संपूर्ण प्रक्रिया के संपन्न होने तक बल में लगभग 9,400 नए युवाओं को भर्ती किया जाएगा तथा बल के अनेक पदाधिकारियों को भी पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इससे निश्चित रूप से सीमांत क्षेत्रों के स्थानीय युवकों को भी बल में भर्ती होने तथा देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देने का सुअवसर प्राप्त होगा।

साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों के मन में सुरक्षा की भावना बढेगी तथा इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में भी गति आएगी। इन नई बटालियनों के स्थापित होने से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नौजवानों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और संपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को भी बल मिलेगा।

सीमावर्ती इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों एवं आधारभूत संरचना के दृष्टिगत भारत-चीन सीमा पर प्रभावी चौकसी, सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था एवं सघन पैट्रोलिंग सुनिश्चित करने के लिए आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों की संख्या बढाने, उनके पारस्परिक अंतर को कम करने एवं उनको सीमा के और समीप स्थापित किए जाने की नितांत आवश्यकता है। आईटीबीपी की 47 अग्रिम चौकियों एवं 12 स्टेजिंग कैम्पस को संबंधित राज्य सरकारों एवं वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आगामी तीन वर्षो में चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की बात की गई है। इसे सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।

हम सभी को यह पूर्ण विश्वास है कि आईटीबीपी की पहले से अधिक उपस्थिति से सीमावर्ती ग्रामीण पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ वाइब्रेंट विलेज की योजनाओं से कई अन्य उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मसलन, सभी मौसम अनुकूल सड़क, पेयजल, 247 सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुउद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर- शामिल है। यकीनन, इससे सीमावर्ती गांवों का सर्वांगीण विकास होगा। ■

(लेखक भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पूर्व महानिदेशक हैं। 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री पंचनंदा कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने ITBP और NDRF के महानिदेशक के रूप में कार्य किया और BSF, CRPF, CISF, SPG और CBI में भी कार्य किया।)

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने नागपुर के राष्ट्रीय फायर सर्विस कॉलेज में 17 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में फायर सर्विस, सिविल डिफेन्स तथा होमगार्ड सेवाओं में बहादुरी के साथ विशिष्ट सेवा योगदान देने के लिए सेवाकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया।

28 अप्रैल, 2023 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय में राष्ट्रीय पुलिस मिशन के माइक्रो मिशन का चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रमाणिक द्वारा किया गया। सम्मेलन में ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण दिया। इसमें माइक्रो मिशन से संबंधित अधिकारी, राज्य एवं केंद्रीय पुलिस बलों के 150 सदस्यों ने भाग लिया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी ने 25 अप्रैल, 2023 को सिक्किम की राजधानी गंगटोक के सिविल सचिवालय में समीक्षा बैठक ली।

21 अप्रैल, 2023 को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डॉ एस एल थाउसेन ने जम्मू एफटीआर का दौरा किया। उन्होंने पहले पुंछ में हुई आतंकवादी घटना के संदर्भ में पूरी जानकारी ली और जम्मू क्षेत्र के आईजी सहित अन्य अधिकारियों को भविष्य में ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा तैयारियों के निर्देश दिए।

15 अप्रैल, 2023 को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डॉ एस एल थाउसेन ने तीन बीघा कॉरिडोर में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्हें फलों की टोकरी भेंट की। यह भेंट दो देशों के बीच दोस्ती के संकेत को दर्शाती है।

20 अप्रैल 2023 को INDFPU-2 के 137 BSF कर्मियों को यूएन पीसकीपिंग मेडल से सम्मानित किया गया। यह कार्यकम कैंप, बेनी ऑफ डी आर कॉन्गो में आयोजित किया गया। ब्रिगेडियर जनरल मोडी बेरेथे, हेड ऑफ मॉन्यूस्को पुलिस ने परेड की समीक्षा की और बीएसएफ के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फाच्यूर्ना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व ड्रुक मीडिया प्रा. लि. ग्रेटर नोएडा द्वारा मुद्रित

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Burearu of Police Research & Development India https://bprd.nic.in